



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05092023-248555  
CG-DL-E-05092023-248555

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3784]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 5, 2023/भाद्र 14, 1945

No. 3784]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 5, 2023/BHADRA 14, 1945

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 सितम्बर, 2023

का.आ. 3946(अ).—पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 3 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा दिनांक 17 सितंबर, 2002 की पूर्व अधिसूचना का.आ. 1008(अ) का अधिक्रमण करते हुए, केन्द्र सरकार पर्यावरण और वन तथा वन्यजीव की विषय-वस्तु एवं उक्त आदेशों में उल्लिखित तत्संबंधी मुद्दों को शामिल करते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुपालन की निगरानी करने तथा उसको सुनिश्चित करने के प्रयोजन से और उक्त अधिनियम तथा न्यायालय के आदेशों के और प्रभावी कार्यान्वयन हेतु आमतौर पर राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय सरकार को उपाय सुझाने और सिफारिश प्रस्तुत करने के उद्देश्य से रिट याचिका (सिविल) सं. 202/95 में आई.ए. सं. 19602 तथा 174896/2019 में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 18 अगस्त, 2023 के आदेश के अनुपालन में नियुक्त निम्नलिखित सदस्यों को सम्मिलित करके, एतद्वारा 'केन्द्रीय सशक्तता समिति' इसमें इसके पश्चात् समिति के रूप में संदर्भित के नाम से एक स्थायी प्राधिकरण का गठन करती है:

## क) अध्यक्ष:

- i. ऐसा व्यक्ति जिसे पर्यावरण या वन और वन्यजीव के क्षेत्र में विशेष जानकारी और पच्चीस वर्षों का अनुभव हो अथवा ऐसा कोई व्यक्ति जिसे केंद्रीय सरकार और / या राज्य सरकार में कम से कम पच्चीस वर्षों का प्रमाणित प्रशासनिक अनुभव हो।
- ii. अध्यक्ष को केंद्र सरकार द्वारा तीन वर्षों की अवधि के लिए मनोनीत किया जाएगा, जिसे अधिकतम एक और कार्यकाल के लिए बढ़ाया जा सकता है।
- iii. अध्यक्ष की अधिकतम आयु सीमा छियासठ वर्ष है।
- iv. केंद्रीय सरकार द्वारा कम से कम अपर सचिव (वेतन लेवल-15) के स्तर के अधिकारी को अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया जाएगा।

## ख) सदस्य सचिव :

- i. जो सरकार का पूर्णकालिक सेवारत अधिकारी हो, जो भारत सरकार में उप वन महानिरीक्षक अथवा निदेशक से नीचे के रैंक का नहीं हो।
- ii. पर्यावरण अथवा वन और वन्यजीव के क्षेत्र में विशेष ज्ञान के साथ बारह वर्ष से अधिक का अनुभव रखता हो।
- iii. उसे केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा।
- iv. वह समिति का मुख्य समन्वय अधिकारी होगा और इस अधिसूचना को तहत समिति के कार्यों के निष्पादन में सहायता प्रदान करेगा।

## ग) तीन विशेषज्ञ सदस्य :

- i. पर्यावरण, वन और वन्यजीव के क्षेत्रों से एक-एक सदस्य।
- ii. जिसे कम से कम बीस वर्षों का अनुभव हो।
- iii. उसे केन्द्र सरकार द्वारा तीन वर्षों के कार्यकाल के लिए मनोनीत किया जाएगा तथा उस कार्यकाल को इसमें ऊपर निर्धारित आयु-सीमा के अधीन अधिकतम एक और कार्यकाल के लिए विस्तारित किया जा सकता है।
- iv. सदस्य का कार्यकाल उसके छियासठ वर्ष की आयु प्राप्त होने के पश्चात् बढ़ाया नहीं जाएगा।
- v. केन्द्र सरकार द्वारा कम से कम संयुक्त सचिव (वेतन स्तर-14) रैंक के अधिकारी की नियुक्ति होगी और वह समिति के अध्यक्ष के रैंक से नीचे के रैंक का होगा।

## 2. समिति निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग करेगी और निम्नलिखित कार्य निष्पादित करेगी :

क. भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा टी.एन. गोदावर्मन तिरूमलपाद बनाम भारत संघ एवं अन्य के मामले में रिट याचिका (सिविल) सं. 202/1995 और 171/1996 में समिति को प्रदत्त शक्तियां और उसके कार्य :-

- क) उपर्युक्त मामलों में उच्चतम न्यायालय के आदेशों के कार्यान्वयन की निगरानी करना तथा गैर-अनुपालन संबंधी रिपोर्टों को समुचित कार्रवाईयों हेतु केन्द्रीय सरकार के समक्ष प्रस्तुत करना;
- ख) किसी पीड़ित व्यक्ति द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुत किंहीं आवेदनों पर कार्रवाई करना तथा जहां आवश्यक हो, उस मामले में केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करना;
- ग) इस आदेश के तहत समिति को प्रदत्त शक्तियों के प्रभावकारी प्रयोग के प्रयोजन से समिति निम्नलिखित कार्य करेगी:

- i. किसी व्यक्ति या संघ अथवा राज्य सरकार या अन्य किसी कार्मिक से किसी भी दस्तावेज़ की मांग करना।
  - ii. स्थल-विशेष का निरीक्षण करना।
  - iii. अपने कार्य के संबंध में किसी भी व्यक्ति (व्यक्तियों) या कार्मिक (कार्मिकों) से अपेक्षित सहयोग या उपस्थिति की मांग करना।
  - iv. विशिष्ट मुद्दों पर कार्रवाई करने के लिए एक या अधिक व्यक्तियों को विशेष रूप से आमंत्रित व्यक्तियों के तौर पर सहयोजित करना।
  - v. जहां व्यावहारिक हो, वन या वन्यजीव या पर्यावरण संबंधी विषयों से संबंधित कार्य को देखने वाले राज्य सरकार के सचिव या उनके प्रतिनिधि या राज्य के प्रधान मुख्य वन-संरक्षक को राज्य-विशेष से संबंधित मुद्दों पर कार्रवाई करने के लिए विशेष-आमंत्रित व्यक्तियों के तौर पर सहयोजित करना।
  - vi. उपर्युक्त मामलों में इस अधिनियम एवं सर्वोच्च न्यायालय के अन्य आदेशों के और अधिक प्रभावी कार्यान्वयन हेतु समान्यतः राज्य तथा केंद्र सरकार को उपायों के संबंध में सुझाव या सलाह देना।
- ख. समय-समय पर, केंद्र सरकार द्वारा समिति को विनिर्दिष्ट किसी मुद्दे की जांच करना और उसके संबंध में सुझाव या सलाह देना।
3. राज्य अथवा केंद्र सरकार को केंद्रीय सशक्तता समिति का कोई सुझाव अथवा अनुशंसा स्वीकार न होने की स्थिति में, सरकार उनकी अस्वीकृति के कारणों को लिखित में प्रस्तुत करेगी और केंद्र सरकार का ऐसा निर्णय अंतिम होगा।
  4. केन्द्रीय सशक्तता समिति की अनुशंसा के साथ राज्य सरकार के निर्णय के स्थगन की स्थिति में, मामले को केंद्र सरकार को प्रस्तुत किया जाएगा और केंद्र सरकार का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।
  5. समिति के सदस्य उनकी निजी क्षमता में नियुक्त किए जाएंगे और यह समिति दिल्ली-स्थित अपने मुख्यालयों सहित पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में केंद्र सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्य करेगी।
  6. अध्यक्ष और सदस्यों को देय वेतन, भत्ते और अन्य अनुलाभ तथा सेवा के नियम और शर्तें ऐसी होंगी जो निर्धारित की जा सकती हैं, बशर्ते कि अध्यक्ष या सदस्य के न तो वेतन, भत्ते और न ही अनुलाभ और सेवा के अन्य नियम और शर्तों में ऐसा अंतर होगा जिससे उनकी नियुक्ति के बाद उन्हें किसी प्रकार की हानि हो।
  7. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय समिति के लिए उपयुक्त और पर्याप्त कार्यालय का स्थान और समिति को सौंपे गए कार्यों और शक्तियों के निर्वहन के लिए आवश्यक कार्यबल, बजटीय सहायता और बुनियादी ढांचा प्रदान करेगा।
  8. सदस्यों और सहायक कर्मचारियों के वेतन या पारिश्रमिक सहित समिति के कामकाज पर होने वाले व्यय का वहन पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा किया जाएगा।
  9. यह समिति, केंद्र सरकार को तिमाही रिपोर्टें प्रस्तुत करेगी और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय समिति के कामकाज की आवधिक समीक्षा और लेखा परीक्षा करेगा।
  10. समिति का क्षेत्राधिकार पूरे भारत में होगा।

[ई. एफ. सं. 13-12/2022-एसयू]

आर. रघु प्रसाद, वन महानिरीक्षक

**MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE****NOTIFICATION**

New Delhi, the 5th September, 2023

**S.O. 3946(E).**— In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1988) (hereinafter referred to as the said Act) and in super-session of earlier notification S.O. 1008 (E) dated 17<sup>th</sup> September, 2002, the Central Government hereby constitutes a permanent Authority to be known as the 'Central Empowered Committee', (hereinafter referred to as the Committee), consisting of the following members appointed in pursuance of the Hon'ble Supreme Court's order dated 18<sup>th</sup> August, 2023 in I. A. NOS. 196062 AND 174896/2019 in Writ Petitions (Civil) No. 202/95 for the purposes of monitoring and ensuring compliance of the orders of the Hon'ble Supreme Court covering the subject matter of Environment, Forest and Wildlife, and related issues arising out of the said orders and to suggest measures and recommendations generally to the State, as well as Central Government, for more effective implementation of the Act and other orders of the Court.

a) Chairman:

- i. having special knowledge and experience of twenty five years in the field of Environment or Forest and Wildlife OR a person with a proven administrative experience of not less than twenty-five years in the Central Government and/or State Government.
- ii. shall be nominated by the Central Government for a tenure of three years, which can be extended maximum for one more tenure.
- iii. maximum age of the Chairman shall be sixty six years.
- iv. shall be appointed at a level not below the rank of Additional Secretary (Pay level-15) in the Government, by the Central Government.

b) Member Secretary:

- i. shall be a full-time serving officer of the Government not below the rank of Deputy Inspector General of Forests or Director in the Government of India.
- ii. having special knowledge in the field of Environment or Forest and Wildlife experience with not less than twelve years.
- iii. to be appointed by the Central Government.
- iv. shall be the Chief Coordinating Officer of the Committee and shall assist the Committee in the discharge of its functions under this Notification.

c) Three Expert Members:

- i. one each from the fields of the Environment, Forest and Wildlife.
- ii. with experience of not less than twenty years.
- iii. they will be nominated by the Central Government for a tenure of three years and can be extended maximum for one more tenure subject to the age limit prescribed herein above.
- iv. tenure of the member shall not exceed till attaining the age of sixty six years.
- v. shall be appointed at level not below the rank of Joint Secretary (Pay level-14) by the Central Government and shall be below the rank of the Chairman of the committee.

2. The Committee shall exercise the following powers and perform the following functions:-

- A. Powers and functions conferred upon the Committee by the Hon'ble Supreme Court of India in Writ Petition (Civil) No. 202/1995 and 171/1996 in the case of T. N. Godavarman Thirumalpad Vs. Union of India and others :-
  - a) to monitor the implementation of Supreme Court's orders in above matters and place reports of noncompliance before the Central Government for appropriate actions;
  - b) to deal with any applications made to it by any aggrieved person and wherever necessary, to make a report to the Central Government in that matter;
  - c) for the purposes of effective discharge of powers conferred upon the Committee under this order; the Committee can:-

- i. call for any documents from any persons or the government of the Union or the State or any other official.
  - ii. undertake site inspection.
  - iii. seek assistance or presence of any person(s) or official(s) required by it in relation to its work.
  - iv. co-opt one or more persons as special invitees for dealing with specific issues.
  - v. co-opt, wherever feasible, the Secretary of the State Government dealing with the subjects related to Forest or Wildlife or Environment or his representative or the Principal Chief Conservator of Forests of the State as special invitees while dealing with issues pertaining to a particular State.
  - vi. to suggest or recommend measures generally to the State as well as Central Government, for the more effective implementation of the Act and other orders of the Supreme Court in above matters.
- B. to examine and advise or recommend on any issue referred to the Committee by the Central Government, from time to time.
3. In case any suggestion or recommendation of the Central Empowered Committee, not acceptable to the State or Central Government, the Government shall give reasons in writing for not accepting the same and such decision of the Central Government shall be final.
4. In case of the deferment of the decision of the State Government with the recommendation of the Central Empowered Committee, the matter shall be referred to the Central Government and the decision of the Central Government shall be final and binding.
5. The members of the Committee are appointed in their personal capacity and the Committee shall function under the administrative control of the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change with its headquarters at Delhi.
6. The salaries, allowances payable to; and the other perks and terms and conditions of service of, the Chairperson and Members, shall be such as may be prescribed, provided that neither the salary, allowances nor perks and the other terms and conditions of service of the Chairperson or a Member shall be varied to his disadvantage after his appointment.
7. The Ministry of Environment, Forest and Climate Change shall provide suitable and adequate office accommodation for the Committee and requisite manpower, budgetary support and infrastructure to discharge the functions and powers delegated to the Committee.
8. The expenditure incurred on the working of the Committee including salary or remuneration to the members and supporting staff, will be met by Ministry of Environment, Forest and Climate Change.
9. The Committee shall submit quarterly reports to the Central Government and the Ministry of Environment, Forest and Climate Change shall undertake periodical review and audit on the functioning of the Committee.
10. The jurisdiction of the Committee shall extend to the whole of India.

[E. F. No. 13-12/2022-SU]

R. RAGHU PRASAD, Inspector General of Forests